बदहाल ग्रामीण शिक्षा

गांवों में स्कूली शिक्षा को बेहतर करने के सरकारी वादों और दावों के बावजूद सच यह है कि आधे छात्र अपनी कक्षा से निचली कक्षाओं की किताबें पढ़ने और गणित के मामूली सवाल हल करने में अक्षम हैं. स्वयंसेवी संस्था प्रथम की सालाना असर रिपोर्ट ने ऐसे अनेक चिंताजनक तथ्यों को रेखांकित किया है. यह रिपोर्ट देश के 596 जिलों के 3,54,944 परिवारों के तीन से 16 साल की उम्र के 5,46,527 बच्चों के सर्वेक्षण पर आधारित है. भले ही कुछ मामलों में गिने-चुने राज्यों के आंकड़े देश के अन्य हिस्सों से बेहतर हैं, पर निचली कक्षाओं में मामूली सुधार को छोड़ दें, तो पूरे देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है. ग्रामीण भारत सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर पर भयावह पिछड़ेपन से लगातार जूझ रहा है. ऐसे में किसी कक्षा के आधे या एक फीसदी छात्रों के अपने से निचली कक्षा के पाठ को पढ़ने में पहले की तुलना में सक्षम होने के आंकड़े से संतोष करना या उसे उपलब्धि मानना देश के भविष्य के प्रति आपराधिक लापरवाही करना होगा. सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा के अधिकार कानून, शिक्षा अधिकर की वसूली जैसे उपायों के बावजूद अगर ग्रामीण छात्र शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, तो यह सरकार और समाज की सोच और दिशा पर बड़ा सवालिया निशान है. असर रिपोर्ट का एक संकेत यह भी है कि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों- बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि- में समस्या तुलनात्मक रूप से अधिक गंभीर है. झारखंड, बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में तो पढ़ने की क्षमता पिछली रिपोर्ट के आंकड़ों से भी कम हुई है. लेकिन, यह तथ्य भी चिंताजनक है कि केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी स्कूलों में बच्चियों के लिए शौचालय की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है. सरकारी स्कूलों की बदहाली का एक नतीजा बच्चों के निजी स्कूलों की ओर रुख करने के रूप में सामने है. इन स्कूलों पर न तो कोई नियमन है और न ही गुणवत्ता सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था. वहां अभिभावकों को महंगा शुल्क तो चुकाना पड़ रहा है, पर बेहतर शिक्षा की कोई गारंटी नहीं मिलती. बुनियादी पठन-पाठन से रहित छात्रों को कौशल प्रशिक्षण दे पाना भी मुश्किल होगा. हमारा देश उन उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है, जो शिक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) का मामूली हिस्सा ही खर्च करते हैं. इसे बढ़ाने की जरूरत है. इसके बिना शिक्षकों को जरूरी प्रशिक्षण देना और समुचित संसाधन उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सकेगा. यह भी जरूरी है कि पाठ्यक्रम पूरा करने की जगह सीखने की क्षमता बढ़ाना पढ़ाई की प्राथमिकता बने. बढ़ती युवा आबादी को रोजगार और जीवनयापन के बेहतर मौके उपलब्ध कराना फिलहाल एक गंभीर चुनौती बनी हुई है. ऐसे में आज प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ रहे 18 करोड़ छात्रों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो अर्थव्यवस्था इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी.

आज प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ रहे 18 करोड़ छात्रों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आनेवाले समय में अर्थव्यवस्था इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी.

सपा-बसपा गठबंधन के मायने

नीरजा चौधरी
वरिष्ठ पत्रकार
neerja_chowdhury@yahoo.com

भारतीय राजनीति में सपा-बसपा का गठबंधन ऐतिहासिक कहा जा सकता है. दोनों पार्टियों की विचारधाराएं अलग-अलग हैं और क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति करने के तरीके भी अलग-अलग हैं. इन दोनों का गठबंधन निश्चित रूप से भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है, बशर्ते इन दोनों के बीच खींचतान कम-से-कम हो.

साल 2014 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा का वोट शेयर जहां 42.6 प्रतिशत था, तो वहीं सपा-बसपा का मिलाकर भी 42 प्रतिशत था. यानी अगर इस समीकरण को देखें, तो सपा-बसपा गठबंधन और भाजपा के बीच बराबरी की लड़ाई हो सकती है, जिससे उत्तर प्रदेश में आधे सीटों का सीधा नुकसान भाजपा को हो सकता है. यहां एक और महत्वपूर्ण बात है. अगर सपा-बसपा के साथ राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) भी आती है (जिसकी संभावना है), तब तो यह गठबंधन भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकता है. अब सवाल यह है कि इस गठबंधन को लेकर मतदाताओं के मन में क्या है? यह देखनेवाली बात होगी कि किस पार्टी का वोट बैंक किसी और तरफ ट्रांसफर होता है या नहीं. बसपा का वोट बैंक कहीं और जाना नहीं है. लेकिन, सपा के मतदाता छिटक सकते हैं, किस तरफ छिटकेंगे, यह देखना होगा. क्योंकि, साल 2014 में यादवों का कुछ हिस्सा भाजपा की तरफ चला गया था. ऐसे में अभी कुछ ठोस कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि इस गठबंधन से उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान होगा, जिसमें एक कारक खुद वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे.

दूसरी बात यह है कि इस समीकरण में नरेंद्र मोदी की छवि और उनका औरा कितना सेंध लगा पाता है, इसकी गहराई में जाने की जरूरत है. योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो जमीन खोयी है, उसकी भरपाई मोदी कितनी कर पाते हैं, यह तो वक्त बतायेगा. बीते डेढ़-दो साल में ही योगी से काफी लोग नाराज हैं और कई तबके में नाराजगी है. नरेंद्र मोदी की अब भी गुडविल है, लेकिन इसमें भी थोड़ी कमी आयी है. इसलिए यह कहना भी मुश्किल है कि यह गुडविल कितना असर करेगा. हालांकि, अब भी लोग हैं, जो चाहते हैं कि मोदी जी को एक मौका और दिया जाना चाहिए, लेकिन वहीं दलित, गरीब, बेरोजगार युवा, छोटे व्यापारी, किसान आदि लोग नहीं चाहते कि मोदी फिर प्रधानमंत्री बनें. हालांकि, बहुत कुछ चुनाव की घोषणा और इस सरकार के आखिरी बजट पर भी निर्भर करेगा कि मोदी अपनी छवि कितना बरकरार रख पायेंगे. लेकिन, इतना तो तय है कि इन पार्टियों का एक साथ आना भाजपा के लिए एक बुरी खबर है.

जब सपा और बसपा अलग-अलग थीं, तब साल 2014 के आम चुनाव में सपा पांच सीट और बसपा शून्य पर आ गयी थी. लेकिन, इनके इकट्ठा होने से कहानी बदल जायेगी.

जब सपा और बसपा अलग-अलग थीं, तब साल 2014 के आम चुनाव में सपा पांच सीट और बसपा शून्य पर आ गयी थी. लेकिन, इनके इकट्ठा होने से कहानी बदल जायेगी. क्योंकि, इस बार योगी सरकार से लोगों की नाराजगी से एंटी-इन्कम्बैंसी भी होगी. जहां तक यह प्रश्न है कि इन पार्टियों ने बिना कांग्रेस के इतना बड़ा कदम उठाया है, तो इसके पीछे यह समीकरण दिख रहा है कि बीते समय में उत्तर प्रदेश के उप चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस ने भाजपा को शिकस्त दी थी, उससे लगता है कि साल 2014 में कांग्रेस से छिटके मतदाता शायद वापसी करेंगे. हालांकि, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई खास वजूद नहीं है इन दिनों. इसलिए मुझे लगता है कि सपा-बसपा गठबंधन के साथ अगर कांग्रेस भी होती, तो बेहतर समीकरण बनता. वजह- एक तो यह कि कांग्रेस एक तरह से राष्ट्रीय विकल्प तो है ही, और अब तो तीन बड़े राज्य भी उसने भाजपा से ले लिये हैं. यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता उस पार्टी के प्रत्याशी को वोट देना पसंद करेगा, जो भाजपा के प्रत्याशी को हराये. ऐसे में यह जरूर लगता है कि इस बार मुस्लिम मतदाता भी कई सीटों का रुख बदलेंगे, क्योंकि इस वक्त वहां वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. मुसलमान ज्यादातर कांग्रेस को वोट देते रहे हैं, इसलिए अगर सपा-बसपा के साथ कांग्रेस भी होती, तब यह गठबंधन भाजपा को 55-60 सीटों का सीधा नुकसान पहुंचा सकता है. सपा-बसपा कह रही थीं कि कांग्रेस साथ आने के लिए बहुत ज्यादा सीटें मांग रही थी. जाहिर है, इस मसले का समाधान हो सकता था. और मैं तो मानती हूं कि अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे आनेवाले समय में गठबंधन का स्वरूप कुछ बदल भी सकता है. सीटों का ऐलान करने के बाद भी कुछ रास्ता निकल सकता है.

लोग ऐसा मान रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण से भाजपा को फायदा मिलेगा. लेकिन, मेरा मानना यह है कि भाजपा ने यह आरक्षण देकर जो राजनीति की है, उससे सारे सवर्ण उसे वोट नहीं देंगे, बल्कि वे सवर्ण वापसी करेंगे, जो भाजपा से नाराज चल रहे हैं. वैसे भी, दस प्रतिशत आरक्षण को लेकर सवर्णों में एक खींचतान मची हुई है कि पता नहीं इससे कुछ फायदा होगा या नहीं, कितने लोगों को कैसे यह मिलेगा, वगैरह. इससे अभी मारामारी और बढ़ सकती है, क्योंकि अब भी कई जातियां हैं, जो अपने लिए आरक्षण की बड़े जोर-शोर से मांग कर रही हैं. मराठा, पाटीदार, जाट आदि जातियों में आरक्षण की मांग अरसे से है. आरक्षण का मुद्दा आगे और पेचीदा हो सकता है, लेकिन फिलहाल भाजपा की ओर से एक सिग्नल देने की कोशिश की गयी है कि पार्टी सवर्णों के बारे में सोच रही है.

कांग्रेस बार-बार कहती है कि उसने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में 22 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश में, वे सीटें दलित-मुस्लिम-ब्राह्मण बहुल क्षेत्रों की थीं. इसलिए कांग्रेस सोच रही है कि उत्तर प्रदेश में इस चीज को दोहराया जाये, क्योंकि कुछ ब्राह्मण भी भाजपा से नाराज हैं. जाहिर है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो चाहेगी ही कि वह अपने दम पर मजबूत बने और शायद इसीलिए वह गठबंधन में शामिल नहीं हुई है. कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी के लिए खुद को संभालने की हर मुमकिन कोशिश करनी ही चाहिए.

सपा-बसपा गठबंधन के मुद्दे वहीं होंगे, जो इस वक्त विपक्ष के मुद्दे हैं. महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, व्यापार संकट, जीएसटी आदि. भाजपा के लिए अब भी राममंदिर का मुद्दा रहेगा, भले ही मोदी जी ने कहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद ही कुछ होगा. मुझे नहीं लगता कि कोर्ट इतनी जल्दी फैसला देगा, इसलिए इसको भाजपा भुनाती रहेगी. हां, भाजपा इस बात को पकड़े रखेगी कि नरेंद्र मोदी दमदार नेता हैं और उन्हें फिर मौका मिलना चाहिए. लेकिन, उसको अब इसका फायदा कम ही मिलेगा.

(वसीम अकरम से बातचीत पर आधारित)

कर्नाटक संकट के लिए कांग्रेस दोषी

आर राजागोपालन
वरिष्ठ पत्रकार
rajagopalan1951@gmail.com

कर्नाटक का राजनीतिक ड्रामा लोकसभा चुनावों का एक ट्रेलर है- गठबंधन सरकार के गिरने के बारे में राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी ही सुर्खियां हैं. भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां अपनी योजना की सफलता को सुनिश्चित करना चाहती हैं. भाजपा यह दिखाना चाहती है कि गठबंधन चाहे देश के स्तर पर हो या क्षेत्रीय स्तर पर, इसे टूटना ही है. वहीं कांग्रेस यह जताना चाहती है कि 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं होगा और जनता दल (सेक्युलर) के साथ उसका गठबंधन लोकसभा चुनावों तक रहेगा. लोकसभा चुनाव के लिए जनता दल (सेक्युलर) यानी जेडीएस और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे की बातचीत शुरू होते ही कर्नाटक की राजनीति संकटग्रस्त हो गयी. दोनों दलों में तनातनी दिसंबर के मध्य में ही शुरू हो गयी थी. चूंकि, मुख्यमंत्री पद जेडीएस के पास है, इसलिए कांग्रेस उसे अधिक सीटें नहीं देना चाहती है. जेडीएस ने 28 में से 12 सीटें मांगी है. बातचीत आधे-आधे के बंटवारे से शुरू हुई थी. बंटवारे पर खींचतान का नतीजा यह हुआ कि असंतुष्ट अस्थिरता का खेल खेलने लगे. स्वाभाविक रूप से भाजपा ने इसका फायदा उठाया है. कांग्रेस ने मुख्यमंत्री कुमारस्वामी पर किसानों की कर्जमाफी जैसे अपने वादे को पूरा करने का दबाव बनाया था. इसमें सिर्फ 800 किसानों के कर्ज माफ हुए. प्रधानमंत्री मोदी ने जेडीएस पर तंज किया कि कर्नाटक सरकार चुनावी घोषणापत्र को लागू करने में असफल रही है. इस घटनाक्रम से कांग्रेस के पैर उखड़ गये. कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने अपनी बाजी भी खूब खेली. इसी तरह से भाजपा के येदियुरप्पा भी सरकार गिराने की कोशिशों में शामिल हो गये.

पुत्र के राज्य में मुख्यमंत्री बनने से पिता देवगौड़ा प्रधानमंत्री पद के सपने देखने लगे. यह भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या है कि पिता और पुत्र को कैसे संभाला जाये. लखनऊ में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव तथा हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बेटे केटी राव और वाइएसआर कांग्रेस के नेता जगन रेड्डी जैसे युवा नेता लोकसभा सीटों के बारे में बैठकें कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में कोई युवा चेहरा नहीं है. मंत्री पद के लिए पुराने चेहरे ही आपस में भिड़े हुए हैं. कर्नाटक कांग्रेस के लिए लोकसभा सीटों पर समझौता चिंता का विषय नहीं है, वह सिर्फ इस लचर गठबंधन को आम चुनाव तक खींचना चाहती है.

कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्व की विचारधारा का आधार है. राज्य में पहले भाजपा सरकार होने का श्रेय संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं को जाता है. लेकिन, वहां हिंदू चरमपंथ के विरोध में भी मजबूत ताकत मौजूद है. अल्पसंख्यकों की राज्य में बड़ी संख्या है. बंगलुरु में ही मुस्लिम आबादी के घनत्व और हिंदुत्व की भावना बढ़ने से कांग्रेस का संगठनात्मक आधार घटता गया और जेडीएस जैसी तीसरी ताकत का उभार हुआ. कर्नाटक की राजनीति में मौजूदा संकट इस विचारधारात्मक मतभेद से भी सीधे तौर से जुड़ा हुआ है.

साल 2018 में कर्नाटक के मतदाताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जनादेश दिया था. भाजपा को बड़ी जीत मिली थी. लेकिन, कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से घुसकर कुमारस्वामी को सरकार बनाने के लिए उकसाया. दोनों पार्टियों के समर्थक अभी तक किसी स्पष्ट समझदारी पर नहीं पहुंच सके हैं. सरकार गिराने के खेल का यह सार-संक्षेप है. डीके शिवकुमार जैसे असंतुष्ट कांग्रेस नेता, जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ खड़े हो रहे हैं. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी लाचार हैं. या तो वे आंसू बहाते हैं या खुलेआम कहते हैं कि ईश्वर ही कर्नाटक को बचा सकता है. दोनों ने राज्य की राजनीति की गति को रोक दिया है. आखिर देवगौड़ा को राज्य-प्रशासन में क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए? उन्हें पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को कानून-व्यवस्था के बारे में चर्चा करने के लिए अपने घर क्यों बुलाना चाहिए? मुख्यमंत्री कुमारस्वामी पिता द्वारा अपने अधिकारों के हनन को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? कांग्रेस के नेता इन बातों से चिंतित हैं.

अब वे दो सवाल, जो कर्नाटक के लोगों के दिमाग में हैं- क्या कुमारस्वामी सरकार बचेगी? क्या जेडीएस और कांग्रेस के बीच कोई समझौता हो सकेगा? राज्य की नौकरशाही और प्रशासन ठप्प पड़े हुए हैं. कर्नाटक की राजनीति का एक पर्यवेक्षक होने के नाते यह लेखक इतना जरूर कह सकता है कि जो भी हो रहा है, वह विचारधारात्मक मुद्दों की राजनीति नहीं है, बल्कि जाति और धर्म पर आधारित है. लिंगायत और वोक्कालिगा जैसी प्रभावशाली जातियां भी राजनीति द्वारा प्रेरित होकर जिला स्तर पर हस्तक्षेप करती हैं.

कांग्रेस नेतृत्व की नजर चुनावी फंड पर थी, जो किसी तरीके से सरकार गठन का बड़ा कारण था. बीते छह महीने में कांग्रेस को कुछ खेमों से चुनावी धन मिला भी है. लेकिन, इसी बीच कांग्रेस के हाथ में तीन सरकारें- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान- और आ गयीं. अब लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पास धन की कमी नहीं है. निष्कर्ष यह है कि कांग्रेस की रुचि कुमारस्वामी प्रयोग को जारी रखने में नहीं है. इसी कारण सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस इस गठबंधन और सरकार की राह में रोड़े अटका रही है. कर्नाटक को स्थायी सरकार चाहिए और लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी होने चाहिए, ताकि लोग नये चेहरे और नया गठबंधन चुन सकें.

कर्नाटक में जो भी हो रहा है, वह विचारधारात्मक मुद्दों की राजनीति नहीं है, बल्कि जाति और धर्म पर आधारित है. लिंगायत और वोक्कालिगा जैसी प्रभावशाली जातियां भी राजनीति द्वारा प्रेरित होकर जिला स्तर पर हस्तक्षेप करती हैं.

आपके पत्र

देशद्रोही या राष्ट्रद्रोही कौन ?

ये दोनों शब्द समय और सत्ता के सापेक्ष होते हैं. एक ही व्यक्ति एक समय 'देशद्रोही' होता है और वही व्यक्ति सत्ता बदलते ही 'देशभक्त' हो जाता है. सबसे पहला देशद्रोह का मुकदमा तिलक पर चला था और दूसरा महात्मा गांधी पर. गांधीजी पर एक पत्रिका में लेख लिखने के कथित जुर्म में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था. अभी 2010 में तत्कालीन सत्ताधारियों ने आदिवासी, आदिम जातियों और जनजातियों की सेवा करने वाले उस डॉक्टर बिनायक सेन पर कथित 'नक्सलियों' की मदद करने का छद्म और झूठा आरोप लगा कर देशद्रोह का मुकदमा चलाया, जिसे भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 में बाइज्जत बरी कर दिया. इसलिए सत्ता के वर्तमान कर्णधारों द्वारा अपने विरोधी लोगों के विचारों के दमन करने हेतु 'देशद्रोही', 'राष्ट्रद्रोही' का आरोप लगाना आश्चर्य की बात नहीं है. सत्ता के मद में सत्ताधारियों द्वारा अपनी बात निर्भीकतापूर्वक कहना और अन्याय के खिलाफ बोलना ही देशद्रोह है, तो कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य पर झूठे आरोप लगाकर देशद्रोह का मुकदमा चलाना तो कुछ नहीं है.

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

शिक्षा व्यवस्था की स्थिति

असर 2018 की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि देश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय में शिक्षा, शिक्षक और पठन-पाठन की स्थिति चिंताजनक है. प्राथमिक विद्यालय के कक्षा दो के विद्यार्थियों को अक्षर ज्ञान तक नहीं है. वहीं माध्यमिक विद्यालय के कक्षा पांच के विद्यार्थियों को गणित के साधारण घटाव, भाग की जानकारी नहीं है. कक्षा सात-आठ के बच्चे भी हिंदी के बहुत ही साधारण वाक्य और गद्य भी पढ़ने में असहज और असफल पाये गये. झारखंड में भी पठन-पाठन की स्थिति अच्छी नहीं है. ऐसे प्राथमिक विद्यालय लगभग 60 प्रतिशत हैं, जहां मात्र कुल 60-70 बच्चों का नामांकन हैं, उपस्थिति उससे कम है. मध्य एवं उच्च विद्यालय में अनेक विषयों के शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है. सरकारी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था और गुणवत्ता एक दर्दनाक कहानी है.

युगल किशोर, इमेल से

धोनी का करारा जवाब

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर एक शानदार जीत दर्ज की और सीरीज को 1-1 की बराबरी करने में सफल रहा. इस मैच में विराट कोहली ने एक बार फिर शतक लगाकर विपक्षी टीम को अपना लोहा मनवाया. धोनी ने इस मैच में भी अर्धशतकीय पारी खेलकर फिर से यह साबित कर दिया है कि अभी भी उनकी टीम में बहुत जरूरत है क्योंकि मुश्किल घड़ी में कैसे खेलना है, यह उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है. अपने इस प्रदर्शन से उन्होंने अपने आलोचकों पर कड़ा प्रहार किया है, जो उन्हें पहले मैच के हार का कारण बता रहे थे. इसलिए यह जरूरी है कि वर्ल्ड कप से पहले हम अपने खिलाड़ियों को भरपूर सपोर्ट करें न कि उन पर सवाल खड़े कर उनका मनोबल गिरायें.

शुभम गुप्ता, नावागढ़, धनबाद.

बोधि वृक्ष

आपकी योग्यता

संसार में आप जो कुछ भी काम करते हैं, वह सही रूप से तभी कुछ विशेष है, कीमती है, जब आप अन्य लोगों के जीवन पर गहराई से कुछ अच्छा असर डालते हैं. मसलन, क्या आप ऐसा मकान बनाना चाहेंगे, जिसमें कोई रहना ही न चाहे? आप ऐसा कुछ भी बनाना नहीं चाहेंगे, जिसका कोई दूसरा उपयोग ही न करना चाहे, क्योंकि किसी न किसी अर्थ में आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं. आप ऐसा काम करना चाहते हैं, जिससे लोगों के जीवन पर अच्छा असर पड़े. कई लोग अपना जीवन कामकाज और परिवार के बीच बांट लेते हैं, उनके लिए कामकाज सिर्फ धन कमाने के लिए है और परिवार ऐसी जगह है, जहां वे दूसरों के जीवन को छूते हैं, उन पर असर डालते हैं. लेकिन यह भाग सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए. यह जीवन के प्रत्येक भाग के लिए होना चाहिए. आप कुछ भी करें, उससे लोगों के जीवन पर अच्छा असर पड़ना चाहिए, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. आप कितनी गहराई से दूसरों के जीवन को छूते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, उसमें किस हद तक आपकी भागीदारी है. अगर आप अंदर तक गहरे उतरे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप जिस तरह से काम करते हैं, वह अलग ही होगा और आपको आपकी योग्यता के अनुसार पैसा मिलेगा. कभी-कभी आपको वेतन वृद्धि के लिए मांग भी करनी पड़ सकती है, पर सामान्य रूप से यदि लोग समझते हों कि उस विशेष कारोबार या कंपनी के लिए आपकी क्या कीमत है, तो वे आपको उसके अनुसार वेतन देंगे. मान लीजिये,आप एक कंपनी के प्रमुख हैं और किसी कारण से वे आपको पर्याप्त पैसा नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने आपको कंपनी चलाने की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंप रखी है. अब, अगर आप बढ़िया काम कर रहे हैं और दुनिया देख रही है, तो कल कोई भी आपको किसी भी कीमत पर लेने को तैयार होगा. तो यह जरूरी नहीं है कि आपकी कीमत को हमेशा पैसे की दृष्टि से ही आंका जाये.

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

कुछ अलग

सिनेमा के संरक्षण में उदासीन समाज

अरविंद कुमार
पत्रकार
arvindkdas@gmail.com

पिछले दिनों मैथिली फिल्मों की चर्चा चली, तब प्रोफेसर वीर भारत तलवार ने कहा कि 'बहुत पहले 1972-73 में मैंने पटना में एक मैथिली फिल्म देखी थी- कन्यादान. हरिमोहन झा की कहानी थी और संवाद रेणुजी के.' फणीश्वरनाथ रेणु इस फिल्म से जुड़े थे, यह मुझे नहीं पता था. मुझे बस इसकी जानकारी थी कि 'कन्यादान' को पहली मैथिली फिल्म होने का श्रेय है.

बहरहाल, मैंने बड़े भाई से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि जब वे पांच साल के थे, तब यह फिल्म देखी थी, जिसकी धुंधली सी यादें हैं. मां ने कहा कि झंझारपुर (गांव का कस्बा) के 'बांस टॉकिज' में गांव में आयी एक नव वधू के साथ उसने भी यह फिल्म देखी थी.

वर्ष 1965 में फणी मजूमदार ने इस फिल्म का निर्देशन किया था. ऐसा लगता है कि इस फिल्म के बेहद कम प्रिंट बने थे. मैंने इस फिल्म को खोजने की कोशिश की और इस सिलसिले में जब पुणे स्थित 'नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया' से संपर्क साधा, तो उनका कहना था कि उनके डेटा बैंक में ऐसी कोई फिल्म नहीं है. उल्लेखनीय है कि कन्यादान उपन्यास का रचनाकाल सन 1933 का है. इस फिल्म में बेमेल विवाह की समस्या को भाषा समस्या के माध्यम से चित्रित किया गया है. इस फिल्म के गीत-संगीत में प्रसिद्ध लोक गायिका विंध्यवासिनी देवी का भी योगदान था. जाहिर है इस फिल्म की अनुपलब्धता के कारण सिनेमा, जो एक समाज को कलात्मक रूप से रचने और उसकी स्मृतियों को सुरक्षित रखने का एक जरिया है, उससे हमारी पीढ़ी वंचित रह गयी है. इस फिल्म का सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व है.

समकालीन समय में जब भी क्षेत्रीय फिल्मों की बात होती है, तो भोजपुरी का जिक्र किया जाता है. मैथिली फिल्मों की चलते-चलते चर्चा कर दी जाती है. लेकिन, यहां इस बात का उल्लेख जरूरी है कि भोजपुरी और मैथिली फिल्मों के अतिरिक्त साठ के दशक में फणी मजूमदार के निर्देशन में ही 'भईया' नाम से एक मगही फिल्म का भी निर्माण किया गया था.

भारतीय सिनेमा के सौ वर्षों के इतिहास में जब भी पुरोधाओं का जिक्र किया जाता है, तब दादा साहब फाल्के के साथ हीरा लाल सेन, एसएन पाटनकर और मदन थिएटर्स की चर्चा होती है. मदन थिएटर्स के मालिक थे जेएफ मदन. एल्फिंस्टन बायस्कोप कंपनी इन्हीं की थी. पटना स्थित एल्फिंस्टन थिएटर (1919), जो बाद में एल्फिंस्टन सिनेमा हॉल के नाम से मशहूर हुआ, में पिछली सदी के दूसरे-तीसरे दशक में मूक फिल्में दिखायी जाती थीं. आज भी यह सिनेमा हॉल नये रूप में मौजूद है.

बिहार में सिनेमा देखने की संस्कृति शुरुआती दौर से रही है. आजादी के बाद मैथिली-मगही-भोजपुरी में सिनेमा निर्माण भी हुआ, पर बाद में जहां तक सिनेमा के संरक्षण और पोषण का सवाल है, बिहार का वृहद समाज उदासीन ही रहा है.

देश दुनिया से

ट्रंप की धमकी पर तुर्की का करारा जवाब

तुर्की और अमेरिका एक बार फिर आमने-सामने हैं. इसका कारण है कुर्द संगठन. कुर्द आबादी ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की में बसी हुई है. तुर्की के कुर्द अलग देश के लिए लड़ रहे हैं. तुर्की को लगता है कि यदि सीरिया के कुर्द मजबूत हो गये, तो तुर्की के भीतर चलनेवाला कुर्दों का आंदोलन भी मजबूत हो जायेगा. अमेरिका ने सीरियाई कुर्दों की मदद की है. सीरिया में संकट के वर्षों में अमेरिका ने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के नाम से एक हथियारबंद गुट तैयार कर दिया, जो कुर्दों का संगठन है. अमेरिका चाहता है कि इन कुर्दों को सीरिया और तुर्की दोनों के खिलाफ प्रयोग करे, मगर सीरिया इस लड़ाई में सफल रहा और उसने विद्रोही संगठनों को सैनिक कार्रवाई या राजनीतिक समझौते के तहत नियंत्रित कर लिया. अमेरिका अलग-अलग बहानों से उन कुर्दों की भी मदद कर रहा है. तुर्की ने एलान कर दिया है कि वह कुर्दों की शक्ति क्षीण करने लिए उन पर सीरिया के भीतर भी हमला कर सकता है. इस समय अमेरिका और तुर्की के बीच यही मुद्दा तनाव का कारण है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि यदि तुर्की ने कुर्दों पर हमला किया, तो अमेरिका तुर्की की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देगा. इसके जवाब में तुर्की ने कहा है कि वह ऐसा नहीं होने देगा.

World News Arabia

कार्टून कोना

साभार : बीबीसी

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है